Most Immediate
Vidhan Sabha Business

No. Rev. 1-3(Stamp)7/80-II-Loose
Government of Himachal Pradesh.
Revenue Department (Stamp-Regn)

From

The Additional Chief Secy. (Revenue),
Government of Himachal Pradesh.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Dated Shimla – 2, the 29/03/2017

Subject:- The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Bill, 2017
2017-introducation thereof.

Sir,

I am to honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Bill, 2017 in the ensuing session of H.P. Vidhan Sabha. This notice may kindly be allowed in condonation of notice period.

Three duly authenticated copies and 120 Copies of the aforesaid Bill are enclosed herewith for taking further necessary action please.

Yours faithfully,

Encls: As above.

(THAKUR KAUL SINGH)
Revenue Minister, H.P.

Endst. As above: Dated 2017

Copy forwarded to the Principal Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-02 for necessary action and information please.

(Parveen Kumar Taak)
Deputy Secy. (Revenue) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
Tel. No.-0177-2628497.

2017 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. नई धारा 42 क का अन्तःस्थापन।
3. 2017 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2017 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 03 फरवरी, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

नई धारा 42 क का अन्तःस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"42 क. राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले वादों, अपीलों, पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध.—इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा उनकी शासकीय हैसियत से किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन दायर किया जाता है या अन्य अभिवचन या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य अभिवचनों या दस्तावेजों की बाबत कोई न्यायालय फीस प्रभार्य नहीं होगी।"।

2017 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अधिप्रमाणित

(कौल सिंह ठाकुर)
स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री,
हिमाचल प्रदेश।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों या लोक कार्यालयों में दायर किए जाने वाले दस्तावेजों पर न्यायालय फीस उद्गृहीत और प्रभारित की जाती है। धारा 42, उक्त अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित समस्त या किसी फीस को बढ़ाने, कम करने, उसका परिहार या प्रतिदाय करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करती है किन्तु यह राज्य सरकार को न्यायालय फीस के संदाय से छूट नहीं देती है।

माननीय उच्च न्यायालय ने सी.एम.पी.(एम.)नम्बर 322 ऑफ 2016 नामतः एल.ए.सी. एण्ड अदर्ज वर्सिज दीनू एण्ड अदर्ज में तारीख 30–08–2016 को सुनवाई करते समय संप्रेक्षित किया है कि *"Should the Government at the first place, pay the court fee afterall for whose benefit. The amount eventually is only exchanging hands rather being paid from one pocket to other pocket of the State Government who really is the beneficiary of such a long drawn exercise? More particularly when experience shows that the expenditure incurred towards payment of court fee, more particularly of a lesser denomination is far more be several hundred times if not thousand times to the actual amount of court fee to be fixed."* माननीय न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षित किया है *कि "It is high time that the Government should ponder and deliberate on the issue of greater public importance by weighing all the pros and cons and thereafter arrive at conscious decision regarding whether to exempt partly or wholly or not to exempt the State Government from payment of court fee.".*

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा न्यायालय फीस के संदाय के विवाद्यक पर किए गए उपरोक्त संप्रेक्षणों का राज्य हित में परीक्षण किया गया और विचार किया गया कि जहां ऐसी न्यायालय फीस सरकार के खाते में ही जमा की जानी है तो वहां राज्य सरकार की ओर से न्यायालय फीस का संदाय करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह केवल मात्र निधियों का राज्य सरकार की एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में आदान–प्रदान ही है। इसलिए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा दायर किए जाने वाले वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य अभिवचन या दस्तावेज की बाबत न्यायालय फीस के संदाय से राज्य सरकार को और शासकीय हैसियत में इसके अधिकारियों को छूट देने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया था।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को 31 जनवरी, 2017 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 03 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अधिप्रमाणित

(कौल सिंह ठाकुर)
स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री,
हिमाचल प्रदेश।

(ठाकुर कौल सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2017

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

अधिप्रमाणित

कौल सिंह

(कौल सिंह ठाकुर)
स्वास्थ्य, राजस्व एवं विधि मंत्री,
हिमाचल प्रदेश।

(ठाकुर कौल सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2017

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

42. फीसों को कम करने या परिहार करने की शक्ति.––राज्य सरकार इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में वर्णित सब फीसें या उनमें से किसी को भी हिमाचल प्रदेश संघ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में या उनके किसी भाग में समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कम कर सकेगी या परिहार कर सकेगी और उसी रीति में ऐसे आदेश को रद्द कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 3 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Insertion of new section 42A.
3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2017 and savings.

Bill No. 3 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of February, 2017.

Insertion of new section 42A.

2. After section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following new section shall be inserted, namely :—

"42A. Special provision regarding suits, appeals, revision etc. filed by or on behalf of the State Government before the Court.—Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where a suit, appeal, revision, review or other pleading or document is filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers in their official capacity before any court, no court fee shall be chargeable in respect of such suit, appeal, revision, review or other pleading or document under the provisions of this Act.".

Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2017 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(KAUL SINGH THAKUR)
Health, Revenue & Law Minister,
Himachal Pradesh.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The court fee is levied and charged on the documents filed in the Hon'ble High Court and other courts or public offices under the provisions of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968. Section 42 empowers the State Government to enhance, reduce, remit or refund all or any of the fees provided in the First and Second Schedules appended to the said Act, but it does not exempt the State Government from payment of court fees.

The Hon'ble High Court while hearing the CMP(M) No. 322 of 2016 titled as LAC and others Vs. Dinu and others on 30-8-2016 observed that "should the Government at the first place, pay the court fee afterall for whose benefit. The amount eventually is only exchanging hands rather being paid from one pocket to other pocket of the State Government who really is the beneficiary of such a long drawn exercise? More particularly when experience shows that the expenditure incurred towards payment of court fee, more particularly of a lesser denomination is far more be several hundred times if not thousand times to the actual amount of court fees to be fixed." The Hon'ble Court has further observed that "it is high time that the Government should ponder and deliberate on the issue of greater public importance by weighing all the pros and cons and thereafter arrive at conscious decision regarding whether to exempt partly or wholly or not to exempt the State Government from payment of court fee.".

The above observations made by the Hon'ble High Court on the issue of payment of court fee by the State Government was examined and considered in the State interest as there seems to be no logic in payment of court fee on behalf of the State Government where such court fee has to go in the accounts of the Government itself. It is merely exchange of funds from one pocket to other pocket of the State Government. As such, it was decided to make special provision in the said Act to exempt the State Government and its officers in their official capacity from payment of court fee in respect of a suit, appeal, revision, review or other pleading or document filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers under the provisions of the Act *ibid*.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the amendment in the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 had to be made urgently, therefore, H.E. the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017 on 31st January, 2017 which

was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 3rd Feburary, 2017. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(THAKUR KAUL SINGH)
Minister-in-Charge.

(KAUL SINGH THAKUR)
Health, Revenue & Law Minister,
Himachal Pradesh.

SHIMLA :

Dated....., 2017.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act,1968 (Act No. 8 of 1968).

(KAUL SINGH THAKUR)
Health, Revenue & Law Minister,
Himachal Pradesh.

(THAKUR KAUL SINGH)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

The..........., 2017.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES ACT, 1968 (ACT NO. 8 OF 1968) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section :

42. Power to reduce or remit fees.—The State Government may, from time to time by notification in the Official Gazette, reduce or remit, in the whole or any part of the Union territory of Himachal Pradesh, all or any of the fees mentioned in the First and Second Schedules to this Act annexed, and may in like manner cancel or vary such order.